*वर्ष 2018-19 में निजी कॉर्पोरेट निवेश: धीमी वसूली जारी**

बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य स्रोतों द्वारा मंजूर की गई परियोजना लागतों की तुलना में निजी कंपनियों और संयुक्त कारोबार क्षेत्रों के निवेश प्रयोजनों और परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं का पता लगाते हुए इस आलेख में यह पाया गया है कि वर्ष 2018-19 में परिकल्पित पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में मामूली सुधार आया है। इसमें राष्ट्रीय आय खातों में परिकल्पित कैपेक्स तथा वास्तविक कैपेक्स के बीच अंतर्निहित संबंधों की भी जांच की गई है।

प्रस्तावना

निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र का पूंजीगत व्यय अर्थव्यवस्था में निवेश परिवेश का प्रमुख वाहक है, और यह उन मूल भावनाओं का द्योतक है जो उद्यमिता ऊर्जाओं और कारोबारी मनोभावों/विचारों को प्रभावित करती हैं। चूंकि कंपनियों के प्रकाशित वार्षिक लेखों से कैपेक्स के बारे में सूचना काफी विलंब से उपलब्ध हो पाती है, इसलिए पूरे देश में प्रचलित सर्वोत्तम प्रथा यह है कि निवेश प्रयोजनों और अन्य संबंधित कारकों, जैसे क्षमता के उपयोग और मांग के संकेतकों के आधार पर कॉर्पोरेट निवेश पूर्वानुमान जेनेरेट किए जाएं (बार्न्स एंड ईलिस, 2005; ऑरिज़योएंड स्टीफॅनो,2011; ओस्टरहोम, 2013)।

भारत 1980 के दशक के अंत से ही निवेश प्रयोजनों के मूल्यांकन और पूर्वानुमान के लिए सर्वेक्षण के प्रयासों के द्वारा इस अंतरराष्ट्रीय अनुभव में भी अग्रणी रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक 1978 से निवेश प्रयोजन प्रत्याशा उपलब्ध कराता रहा है। सारांश यह है कि निवेश प्रयोजनों पर डेटा वित्तीय पहलू – बैंकिंग क्षेत्र और वित्तीय संस्थाओं (एफआई)[1] तथा बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी)[2], विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी) तथा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ), सार्वजनिक प्रस्तावों का फॉलो-ऑन (एफपीओ) और वर्ष के लिए निर्गमित राइट्स से प्राप्त किया जाता है।

डॉ.सी रंगराजन ने 1970 में वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित कॉर्पोरेट परियोजनाओं के समय समंजन पर आधारित अल्पकालिक (एक वर्ष पहले) पूर्वानुमानों की शुरुआत की थी। इस प्रणाली के अंतर्गत कंपनियों द्वारा मूल्यांकन के समय प्रस्तुत की गई प्रत्याशित समंजन योजनाओं के आधार पर उस वर्ष के दौरान किए जाने वाले कैपेक्स के संभावित स्तर का अनुमान प्राप्त किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक परियोजना द्वारा इस सूचना-वर्ग में एक ही बार प्रविष्टि की जाती है, चाहे उसका वित्तपोषण एक से अधिक माध्यमों से किया गया हो। उपर्युक्त में से किसी भी माध्यम से वित्तपोषित न की गई अथवा ₹100 मिलियन से कम आकार की परियोजनाओं को शामिल नहीं किया गया है। ऐसी परियोजनाएं, जिनका निजी स्वामित्व 51 प्रतिशत से कम हो, या जो न्यास, केंद्र या राज्य सरकार का उपक्रम हो, तथा शैक्षणिक संस्थाओं को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। एक नोट करने लायक चेतावनी यह है कि यह मान लिया जाता है कि कंपनियां अपनी प्रत्याशित व्यय योजनाओं का पालन करती हैं। इसके परिणामस्वरूप, यह संभावना रहती है कि कुछ अपेक्षित इरादों का परिणाम वास्तविक निवेश में नहीं होता हो।

इस आलेख में 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के कैपेक्स का अनुमान लगाते हुए इस परंपरा को आगे बढ़ाया गया है। ऐसा करते हुए, इसमें अनुमानित कैपेक्स (परियोजना योजनाओं के आधार पर) और वास्तविक कैपेक्स (जैसाकि राष्ट्रीय लेखा में उपलब्ध है) के बीच संबंध का भी पता लगाया गया है। इसकी प्रति-जांच के रूप में 2017-18 के लिए राष्ट्रीय आय के प्रथम संशोधित अनुमानों के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए वास्तविक निवेश, जो केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) के द्वारा 31 जनवरी 2019 को प्रकाशित किए गए हैं, के साथ अनुमानित कैपेक्स की तुलना की गई है।

---

* एस. सुजीश कुमार और आर. के. सिन्हा, कॉर्पोरेट अध्ययन प्रभाग, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग । इस लेख में प्रस्तुत विचार लेखकों के हैं तथा ये भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। पिछला अध्ययन "निजी कॉर्पोरेट निवेश : 2016-17 में वृद्धि और 2017-18 के लिए संभावनाएं" शीर्षक से भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन के सितंबर 2017 अंक में प्रकाशित किया गया था।

[1] इसमें सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक, प्रमुख निजी बैंक और विदेशी बैंक तथा परियोजना वित्तपोषण में सक्रिय रूप से लिप्त वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं, नामत: भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीएल), भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), पावर फाइनैंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी), रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (आरईसी) तथा भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्ज़िम)।

[2] ईसीबी में रुपये में अंकित बांड (आरडीबी) शामिल हैं।

इस आलेख के शेष हिस्से को चार भागों में बांटा गया है। भाग II में समीक्षाधीन अवधि के दौरान मंजूर या वित्तपोषित की गई परियोजनाओं , उनके वित्तीयन, क्षेत्रों और उद्योगों के अनुसार उनके बंटवारे संबंधी पहलुओं और कॉर्पोरेट निवेश संवृद्धि पर चर्चा की गई है। भाग III में निजी व्यवस्था/ नियोजन और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तुत किए गए हैं। भाग IV में अनुमानित निवेश का समय-श्रृंखला विश्लेषण उपलब्ध कराया गया है। भाग V में अधययन के निष्कर्ष दिए गए हैं।

II. मंजूर की गईं / वित्तपोषित परियोजनाएं

वर्ष 2017-18 के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा ₹1,728 बिलियन की कुल लागत वाले 490 परियोजनाओं के प्रस्ताव मंजूर किए गए। इसके अतिरिक्त, उस वर्ष में 292 कंपनियों द्वारा ₹247 बिलियन के ईसीबी/ एफसीसीबी करार किए गए। इसके अलावा, 51 कंपनियों ने बैंकों और एफआई से वित्त नहीं लिया, किंतु अपनी कैपेक्स जरूरतों के लिए घरेलू इक्विटी निर्गम के माध्यम से ₹16 बिलियन जुटाए। कुल मिला कर, 2016-17 में 916 कंपनियों के कुल ₹2028 बिलियन के निवेश इरादों की तुलना में 2017-18 के दौरान कुल 833 कंपनियों ने निवेश योजनाएं बनाईं, जिनका कुल योग ₹1991 बिलियन रहा (अनुबंध सारणियां 1-4)।

उद्योगवार देखें, तो रसायन और रासायनिक उत्पाद 2017-18 में परियोजनाओं की कुल लागत के 11 प्रतिशत रहे, जो अपने पाँच साल के औसत (2012-13 से 2016-17 के दौरान) 1.7 प्रतिशत से काफी अधिक है। निर्माण क्षेत्र का हिस्सा 2016-17 में 12 प्रतिशत से घट कर 2017-18 में 5.1 प्रतिशत रह गया, जो इस क्षेत्र में निस्तेज गतिविधियां दर्शाता है। इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के भीतर, ऊर्जा क्षेत्र का वर्चस्व बना रहा, हालांकि इसका हिस्सा 2016-17 (45.4 प्रतिशत) और पाँच वर्ष के औसत (43.8 प्रतिशत) स्तर से काफी कम रहा। वर्ष 2017-18 में ऊर्जा क्षेत्र में कम परियोजनाएं मंजूर किए जाने के कारण भी परियोजनाओं की कुल लागत में इसका हिस्सा संकुचित हुआ (चार्ट 1 तथा अनुबंध सारणी 5)।

मंजूर की गई परियोजनाओं की कुल लागत मेगा प्रोजेक्ट्स की मौजूदगी से चालित होती है, जो सामान्यत: लंबे समय तक चलते हैं, जैसाकि उनकी अवस्था वर्णन फेज़िंग प्रोफाईल से देखा जा सकता है। अधिक मूल्य (₹10 बिलियन – ₹50 बिलियन) की 44 परियोजनाएं थीं, जिनका कुल परियोजना लागत में 44.1 प्रतिशत हिस्सा था। बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय मंजूरी प्राप्त परियोजनाओं का आकार-वार वितरण मेगा प्रोजेक्ट (₹50 बिलियन और उससे ऊपर) की संख्या में गिरावट (2016-17 में 5 की तुलना में 2017-18 में तीन) दर्शाता है; तथापि, कुल परियोजना लागत में उनके हिस्से में मामूली वृद्धि हुई है (2016-

चार्ट 1: बैंकों / एफआई द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं की सकल लागत में प्रमुख उद्योगों का हिस्सा

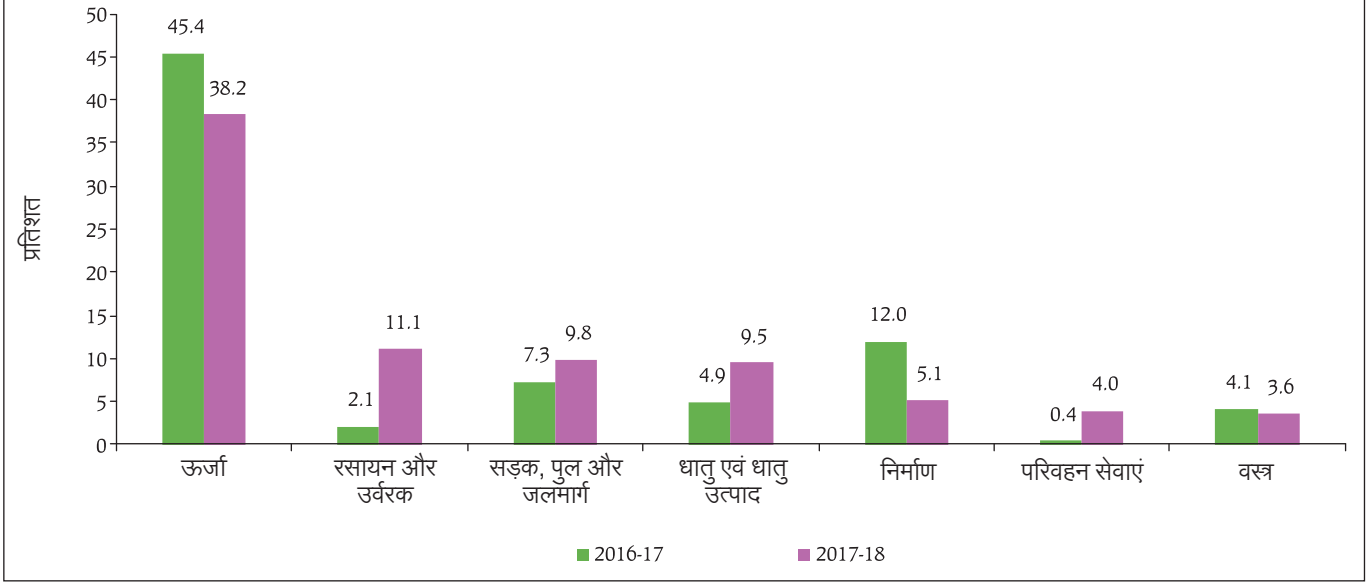

17 में 17.4 प्रतिशत से बढ़ कर 2017-18 में 18.6 प्रतिशत)। वर्ष 2015-16 में गिरावट के बाद 2016-17 और 2017-18 में मेगा प्रोजेक्ट्स के टिकट साइज़ (परियोजना की औसत लागत) में वृद्धि हुई (अनुबंध सारणी 6)।

परियोजना के स्थान का चयन विशेष रूप से कच्चे माल की सुलभता, कुशल श्रम की उपलब्धता, समुचित इन्फ्रास्ट्रक्चर, बाजार का आकार और वृद्धि की संभावना जैसे कारकों के आधार पर किया जाता है। पिछले पाँच वर्षों (2013-14 से 2017-18) में 68 प्रतिशत से अधिक परियोजनाएं महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में शुरू की गईं (चार्ट 2)।

बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा 2017-18 में मंजूर की गई परियोजनाओं की कुल लागत में महाराष्ट्र का हिस्सा सबसे ज्यादा (22.6 प्रतिशत) रहा, उसके बाद क्रम से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और छत्तीसगढ़ आते हैं। गुजरात के हिस्से में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष गिरावट दर्ज की गई। हाल की अवधि में 'बहु-राज्यीय' परियोजनाओं का हिस्सा कम हुआ है, जो संभवत: विभिन्न प्राधिकारियों से क्लीयरेन्स प्राप्त करने में आने वाले अवरोधों को दर्शाता है (चार्ट 3 और अनुबंध सारणी 7)।

बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं की कुल लागत में नई परियोजनाओं में निवेश का हिस्सा सबसे ज्यादा (89.3 प्रतिशत) रहा। कुल परियोजना लागत में विस्तार और आधुनिकीकरण का हिस्सा 9.2 प्रतिशत रहा (अनुबंध सारणी 8)।

बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं के कैपेक्स की फेजिंग प्रोफाइल यह दर्शाती है कि कुल प्रस्तावित व्यय का लगभग 38 प्रतिशत (₹650 बिलियन) 2017-18 में, 24 प्रतिशत (₹419 बिलियन) 2018-19 में तथा 21 प्रतिशत (₹368 बिलियन) उसके बाद वाले वर्ष में खर्च किया जाएगा। वर्ष 2017-18 में मंजूर की गई परियोजनाओं की कुल लागत का लगभग 17 प्रतिशत 2014-15 से 2016-17 के दौरान खर्च किया गया था।

योजनाबद्ध व्यय में से 2017-18 के लिए परिकल्पित सकल कैपेक्स में पिछले वर्ष कि तुलना में मामूली गिरावट देखी गई, आंशिक रूप से जो बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूरियों में कमी के कारण हुई। वर्ष 2017-18 में अंतरराष्ट्रीय बांड बाजारों से जुटाए गए संसाधनों से किए जाने वाले कैपेक्स में एक वर्ष पहले की तुलना में 7 प्रतिशत की कमी आई। पूंजी बाजार (इक्विटी रूट) से 2017-18 में ₹19 बिलियन के परिकल्पित कैपेक्स का वित्तपोषण उपलब्ध हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम था।

चार्ट 2: बैंकों / एफआई द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं की लागत (प्रतिशत में) का राज्य-वार वितरण

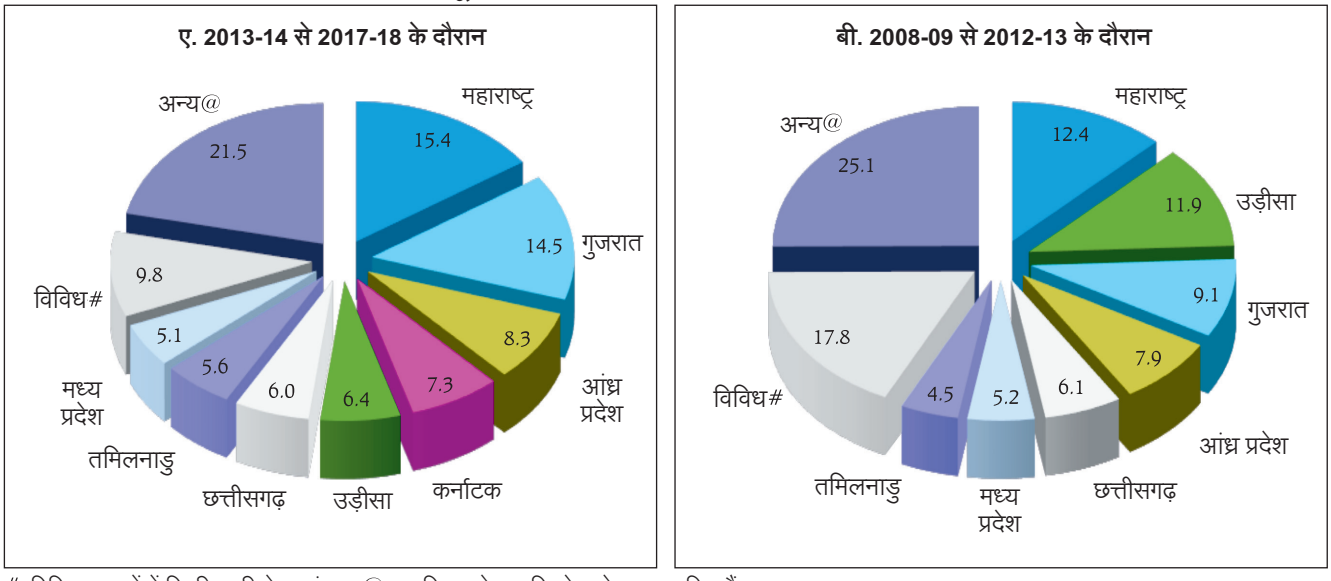

#: विभिन्न राज्यों में वितरित परियोजनाएं। @: 5 प्रतिशत से कम हिस्से वाले राज्य शामिल हैं।

चार्ट 3: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर परियोजनाओं की सकल लागत में प्रमुख राज्यों का हिस्सा

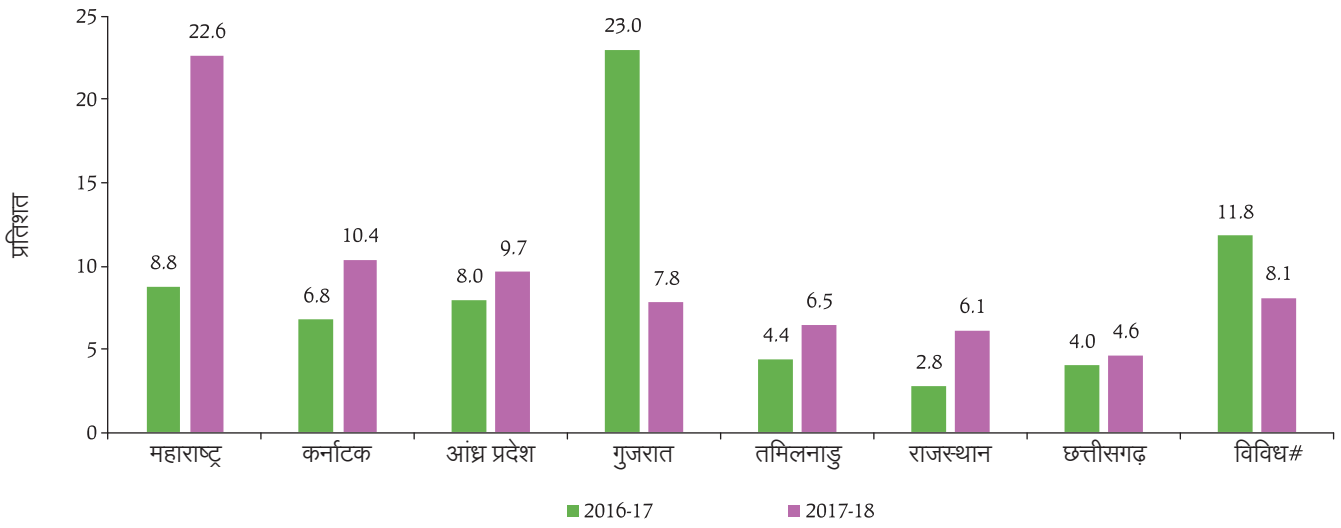

#: 'विविध राज्यों' में वितरित योजनाएं

सारांश में, यह आकलन किया गया है कि वर्ष 2017-18 में निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा कुल ₹ 1,487 कैपेक्स खर्च किया जाएगा, जिसमें से ₹802 बिलियन वर्ष के दौरान की नयी मंजूरी से संबंधित था । निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की कैपेक्स योजनाओं में लगातार सातवें वर्ष वार्षिक संकुचन दर्ज किया गया। तथापि, पहले ही शुरू की गयी पाइपलाइन परियोजनाओं[3] से अनुमानित कैपेक्स ने पिछले वर्ष की पाइपलाइन परियोजनाओं की तुलना में सुधार दर्शाया। पूर्ववर्ती वर्षों में मंजूर की गई पाईपलाईन परियोजनाओं के आधार पर, वर्ष 2018-19 में नियोजित कैपेक्स ₹ 792 बिलियन हो सकता है जो पिछले वर्ष (₹ 685 बिलियन) की स्थिति में सुधार दर्शाता है। आगे बढ़ते हुए 2018-19 में मंजूर की जा रही नई परियोजनाओं में 2018-19 में कॉर्पोरेट निवेश का स्तर भी इस वर्ष के लिए कुल कैपेक्स को प्रभावित करेगा।

वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं ने कुल ₹914 बिलयन की 190 परियोजनाएं मंजूर की। वित्तपोषण के तीन चैनल (अर्थात. बैंक/वित्तीय संस्था, इसीबी/एफसीसीबी/ आरडीबी और आइपीओ) (सारणी 1) के माध्यम से ₹ 1.158 बिलियन के कुल 451 निवेश प्रस्ताव मंजूर किए गए।

III. निजी नियोजन और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश द्वारा वित्तपोषित कॉर्पोरेट निवेश

हाल के वर्षों में, बांड और डिबेंचरों जैसे कर्ज लिखतऔर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) ने कैपेक्स वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों के रूप में प्राधान्य हासिल किया है । 2013-14 से 2016-17 तक की अवधि के दौरान ऋण के निजी नियोजन (बांड और डिबेंचर) के माध्यम से धन जुटाने में काफी वृद्धि हुई,

सारणी 1: एच1:2018-19 में बैंकों /एफआई /ईसीबी /एफसीसीबी /आरडीबी/आईपीओ द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के कैपेक्स के चरण*

	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर / करार की गई राशि ₹ बिलियन	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2019-20 के आगे
बैंक/एफआई	190	914	6	51	46	399	225	187
ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी	176	239				233	6	
आईपीओ	85	5				4	1	
कुल	**451**	**1,158**	**6**	**51**	**46**	**636**	**232**	**187**

*: अनंतिम आंकड़े।

[3] पाइपलाइन परियोजनाएं वे परियोजनाएं हैं, जो पहले ही कार्यान्वयन के लिए ली जा चुकी हैं। पाइपलाइन परियोजनाओं से कैपेक्स किसी दिए गए वर्ष के लिए अनुमानित राशि है, जो उस मंजूरी वर्ष से पहले मंजूर की जा चुकी है।

सारणी 2: निजी नियोजन और एफडीआई (बिलियन ₹ में)

अवधि	कर्ज - निजी नियोजन*	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश**
2011-12	270	1,651
2012-13	591	1,219
2013-14	560	1,475
2014-15	974	1,891
2015-16#	1,175	2,623
2016-17#	1,544	2,917
2017-18#	1,299	2,889
एच1:2018-19#	549	1,551
(एच1:2017-18)#	(584)	(1,625)

*: निजी क्षेत्र की केवल विनिर्माण तथा सेवा कंपनियों के लिए।
**: एफडीआई इनफ्लो में ईक्विटी पूंजी शामिल हैं।
#: अनंतिम आंकड़े।
स्रोत : प्राइम डाटाबेस तथा भारत सरकार।

लेकिन यह 2017-18 और 2018- 19 की पहली छमाही में यह कम हुआ (सारणी 2)।

IV. परिकल्पित निवेश का टाइम सीरीज विश्लेषण

क्या परिकल्पित कैपेक्स और वास्तविक वसूली के बीच कोई संबंध है? वर्ष 1991-92 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में परिकल्पित कैपेक्स[4] और निजी क्षेत्र के सकल नियत पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) के संबंध में एक वर्ष बाद के अनुमानों में कुछ चुनी हुई अवधियों के लिए विचलन दिखाई देता है, विशेषत: हाल के वर्षों में। तथापि, दीर्घावधि में इन दोनों सीरीज में सह-गतिविधि प्रतीत होती है। (चार्ट 4)

ऑगमेंटेड डिकी-फुलर (एडीएफ) यूनिट रूट टेस्ट से पता चलता है कि दोनों सीरीज (परिकल्पित निवेश और प्राप्त निवेश) अपनी पहली असमानता में अपरिवर्तित हैं। जैसे। (1) हालांकि, एडीएफ और फिलिप्स-पेरोन (पीपी) यूनिट रूट टेस्ट द्वारा दिए गए अलग-अलग परिणामों के मद्देनजर परिकल्पित निवेश स्पष्ट रूप से I(1) नहीं है । इसके संबंध की जांच एक ऑटोरिग्रेसीव डिस्ट्रिब्यूटेड लैग (ARDL) फ्रेमवर्क में की जाती है, जो छोटे नमूनों के साथ लंबे समय तक चलने वाले संबंध और त्रुटि सुधार प्रक्रिया (पेसारन और अन्य 2001) का ठोस अनुमान लगाता है। यह लंबे समय तक चलने वाले संबंध के कार्य-कारण की सटीक दिशा निर्धारण करने में भी सहायता करता है। उपयुक्त एआरडीएल मॉडल, अर्थात एआरडीएल (1, 2) को अकाइके इन्फारमेशन क्राइटेरिया (एआईसी) के आधार पर चुना गया था। चयनित एआरडीएल मॉडल से प्राप्त गुणांक अनुमानित संकेतों के साथ सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, एरर करेक्शन मॉडल (ईसीएम) के ईसीएम शब्द पर सांख्यिकीय रूप

चार्ट 4: परिकल्पित तथा वास्तविक निवेश- (वृद्धि दर)

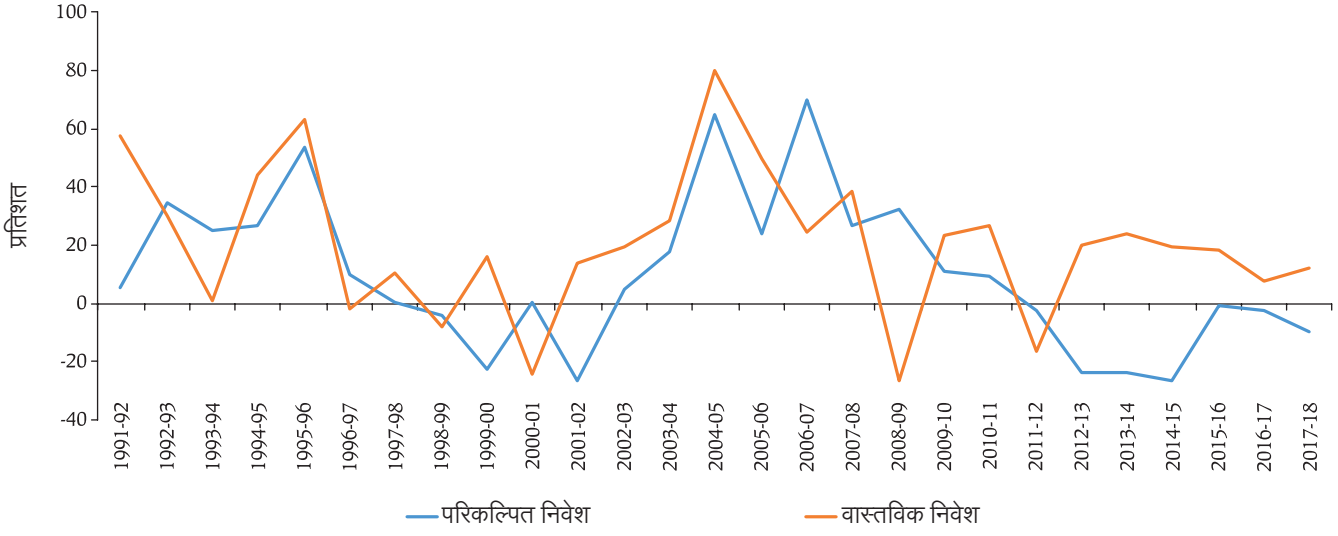

स्रोत : सीएसओ तथा आरबीआई

[4] दीर्घतर समय-श्रृंखला आंकडों की उपलब्धता के कारण बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं के लिए परिकल्पित कैपेक्स लिया गया है।

सारणी 3: एआरडीआई (1,2) मॉडल अनुमान

वेरिअबल	गुणांक	टी-स्टैटिस्टिक	संभावना
दीर्घकालिक गुणांक			
परिकल्पित निवेश	0.345	2.116	0.047
अचल	15.897	4.052	0.000
अल्पकालिक गुणांक			
डी (परिकल्पित निवेश)	0.651	3.184	0.004
डी (परिकल्पित निवेश (-1))	0.439	2.299	0.032
एरेर करेक्शन टर्म	-1.235	-6.102	0.000

आश्रित चर : वास्तविक निवेश
स्वतंत्र चर : परिकल्पित निवेश
समायोजित आर-स्क्वेयर = 0.60, डरबिन-वाटसन स्टैटिस्टिक = 2.102.

से महत्वपूर्ण अल्पकालिक समायोजन मापदंडों के साथ अपेक्षित नकारात्मक चिह्न है। अल्पकालिक डायनेमिक प्रभाव के संकेत लंबे समय तक चलने वाले गुणांक (सारणी 3) के अनुरूप हैं।

मॉडल से निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र (सारणी 4) के परिकल्पित निवेश और प्राप्त निवेश के बीच का संबंध पता चलता है, जो साहित्य के प्रमाण (सत्यनारायण और सावलकर, 2003) के अनुरूप है।

V. निष्कर्ष

इस लेख में प्रस्तुत विश्लेषण से परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं का परिकल्पित कैपेक्स तथा वास्तविक निवेश के बीच का दीर्घकालिक संबंध पता चलता है। इस प्रकार, निवेश के प्रयोजन से कैपेक्स के संबंध में समग्र रूप सेउपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं।

पहले से शुरू की गई पाइपलाइन परियोजनाओं के साथ, 2018-19 की पहली छमाही में स्वीकृत परियोजनाएं, कैपेक्स चक्र में कुछ उगाही दर्शाती हैं। आगे बढ़ते हुए, निजी कंपनियों की पाइपलाइन परियोजनाओं के कारण निवेश गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है।

जैसा कि इन निवेश योजनाओं से पता चलता है मध्यावधि में निवेश चक्र का पुनरुद्धार हो सकता है। कॉर्पोरेट्स और बैंकिंग दोनों क्षेत्रों के तुलन पत्र को मजबूत करने के लिए हाल के प्रयासों से पूंजी निर्माण में तेजी लाने के लिए अनुकूल वातावरण होना चाहिए। 2018-19 की पहली तिमाही में विभिन्न सर्वेक्षणों में बताए

सारणी 4: बाउंड टेस्ट

टेस्ट स्टैटिस्टिक	मूल्य	सिग्निफिकंस (%)	लोअर बाउंड	अपर बाउंड
एफ-स्टैटिस्टिक	11.286	10.0	3.02	3.51
के	1	5.0	3.62	4.16
		2.5	4.18	4.79
		1.0	4.94	5.58

गए क्षमता का बेहतर उपयोग और कारोबारी प्रत्याशाएं भारतीय अर्थव्यवस्था में आने वाले समय में निवेश गतिविधि में नवशक्ति का संकेत दे रही हैं।

References

Aurizio, L. D. and Stefano, I. (2011), "Investment Forecasting with Business Survey Data", Working Paper Number 832, November, Bank of Italy.

Barnes, S. and Ellis, C. (2005), "Indicators of short-term Movements in Business Investment", *Bank of England Quarterly Bulletin,* Spring, 30-38.

Osterholm, P. (2013), "Forecasting Business Investment in the Short Term Using Survey Data", *Working Paper Number 131,* November, National Institute of Economic Research.

Pesaran, M. H. Smith, R. J. and Shin, Y. (2001), "Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships, *Journal of Applied Econometrics,* 16, 289-326.

Rangarajan, C. (1970), "Forecasting Capital Expenditure in the Corporate Sector", *Economic and Political Weekly*, December 19.

Satyanarayana, R and Savalkar, S. V. (2003), "Short-term Forecast of Corporate Investment since 1970's - Three Decades in Retrospect", *Reserve Bank of India Occasional Papers*, 24 (1 & 2), Summer and Monsoon.

अनुबंध

सारणी 1: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा चरणबद्ध रूप से स्वीकृत परियोजनाएं

मंजूरी का वर्ष ↓	परियो-जनाओं की संख्या	मंजूरी के वर्ष में परियोजना की लागत (₹ बिलियन में)	संशोधन / निरसन@ के कारण परियोजना की लागत (₹ बिलियन में)	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19 से आगे
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2009-10 तक	3,350	15,446	12,257 (43.9)	2,736	2065	1191	445	123	34					
2010-11	697	4,603	3,752 (18.5)	286	1,071	1,046	788	464	85	1	9			
2011-12	636	2,120	1,916 (9.6)	57	230	669	554	282	95	29	-			
2012-13	414	1,963	1,895 (3.5)		1	367	567	490	273	112	65	20		
2013-14	472	1,340	1,273 (5.0)			13	151	348	449	199	71	42		
2014-15	326	876	873 (0.4)				1	148	346	259	95	24		
2015-16	346	954	918 (3.7)					38	74	375	286	81	50	14
2016-17	541	1,828	1,792 (2.0)					13	39	254	712	411	216	147
2017-18	490	1,728							6	162	123	650	419	368
कुल जोड़#				**3,079**	**3,367**	**3,286**	**2,506**	**1,906**	**1,401**	**1,391**	**1,361**	**1,228**	**685**	**529**
प्रतिशत में परिवर्तन					**9.4**	**-2.4**	**-23.7**	**-23.9**	**-26.5**	**-0.7**	**-2.2**	**-9.8**	*	

#: कॉलमों के योग किसी वर्ष विशेष में परिकल्पित पूंजीगत व्यय को दर्शाते हैं जिसमें उन परियोजनाओं को शामिल किया गया है जिन्हें अलग-अलग वर्षों में वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। ये प्रत्याशित अनुमान हैं, जिसमें सिर्फ परिकल्पित निवेश को शामिल किया गया है। ये वास्तव में प्राप्त / प्रयुक्त अनुमान से भिन्न हैं।

*: 2018-19 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2018-19 में जिन पूंजीगत व्यय के प्रस्तावों को मंजूर किए जाने की संभावना है, वे उपलब्ध नहीं हैं।

@: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े निरसन का प्रतिशत हैं।

सारणी 2: ईसीबी/ एफसीसीबी/आरडीबी** के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं * के पूंजीगत व्यय की चरणबद्ध स्थिति

निम्नलिखित वर्षों में ऋण संविदा की गई ↓	कंपनियों की संख्या	कुल संविदा ऋण (₹ बिलियन में)	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19 से आगे
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2009-10 तक	2,230	2,063	288	144	22	2							
2010-11	302	316		174	109	27	5						
2011-12	438	379			252	128	19	1					
2012-13	519	660				378	203	63	13				
2013-14	563	803					562	210	31	3			
2014-15	478	572						368	168	32	6		
2015-16	314	388							290	73	26		
2016-17	346	224								150	60	12	2
2017-18	292	247									148	88	11
कुल&	**5,482**	**5,653**	**288**	**318**	**383**	**534**	**788**	**642**	**502**	**258**	**240**	**100**	**13**
प्रतिशत में परिवर्तन				**10.5**	**20.5**	**39.4**	**47.5**	**-18.6**	**-21.8**	**-48.6**	**-7.0**	#	

*: वे परियोजनाएं जिन्हें बैंको / वित्तीय संस्थानों से सहायता प्राप्त नहीं हुई थी।

**: रुपये में अंकित बॉण्ड 2016-17 से शामिल किए गए।

#: 2018-19 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2018-19 में जिन पूंजीगत व्यय के प्रस्तावों को मंजूर किए जाने की संभावना है वे उपलब्ध नहीं हैं।

&: अनुमान प्रत्याशित हैं, इनमें केवल परिकल्पित निवेश शामिल किए गए है। ये वास्तव में प्राप्त / प्रयुक्त अनुमानों से भिन्न हैं।

सारणी 3: इक्विटी निर्गमों के माध्यम से धन उपलब्ध कराई गई परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय की चरणबद्ध स्थिति*

निम्नलिखित वर्ष के दौरान जारी इक्विटी ↓	कंपनियों की संख्या	परिकल्पित पूंजीगत व्यय (₹ बिलियन में)	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19 से आगे
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2009-10 तक	198	232	14	7	1								
2010-11	30	21	1	12	6	2							
2011-12	21	10		2	5	3							
2012-13	25	11				5	5	1					
2013-14	21	5						4	1				
2014-15	24	11						2	6	3			
2015-16	40	45							6	28	11		
2016-17	29	12								5	4	3	
2017-18	51	16									4	4	8
कुल*	**439**	**363**	**15**	**21**	**12**	**10**	**5**	**7**	**13**	**36**	**19**	**7**	**8**
प्रतिशत में परिवर्तन				**40.0**	**-42.9**	**-16.7**	**-50.0**	**40.0**	**85.7**	**176.9**	**-47.2**	**#**	

*: वे परियोजनाएं जिन्हें बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/एफसीसीबी/आरडीबी से सहायता प्राप्त नहीं हुई थी।
#: 2018-19 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2018-19 में जिन पूंजीगत व्यय के प्रस्तावों को मंजूर किए जाने की संभावना है वे उपलब्ध नहीं हैं।
&: ये प्रत्याशित अनुमान हैं जिसमें सिर्फ परिकल्पित निवेश को शामिल किया गया है। ये वास्तव में प्राप्त/प्रयुक्त अनुमान से भिन्न हैं।

सारणी 4: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/आईपीओ/ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी* के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय को चरणबद्ध करना

मंजूरी का वर्ष ↓	कंपनियों की संख्या	परियोजना लागत (₹ बिलियन में)	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19 से आगे
	बैंक/वित्तीय संस्थाएँ/ईसीबी/ एफसीसीबी/ आरडीबी/ आईपीओ												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2009-10 तक	7,310	5,864	3,038	2,216	1,214	447	123	34	-	-	-	-	-
2010-11	1,029	4,089	287	1,257	1,161	817	469	85	1	9	-	-	-
2011-12	1,095	2,305	57	232	926	685	301	96	29	-	-	-	-
2012-13	958	2,566	-	1	367	950	698	337	125	65	20	-	-
2013-14	1,056	2,081	-	-	13	151	910	663	231	74	42	-	-
2014-15	828	1,456	-	-	-	1	148	716	433	130	30	-	-
2015-16	700	1,351	-	-	-	-	38	74	671	387	118	50	13
2016-17	916	2,028	-	-	-	-	13	39	254	867	475	231	149
2017-18	833	1,991	-	-	-	-	-	6	162	123	802	511	387
कुल#			**3,382**	**3,706**	**3,681**	**3,051**	**2,699**	**2,050**	**1,906**	**1,655**	**1,487**	**792**	**549**
प्रतिशत में परिवर्तन				**9.6**	**-0.7**	**-17.1**	**-11.5**	**-24.1**	**-7.0**	**-13.2**	**-10.2**	@	

*: 2016-17 से आरडीबी शामिल किए गए है।
@: 2018-19 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2018-19 तक स्वीकृति की संभावनाओं वाली परियोजनाओं से संबंधित पूंजीगत व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
#: आकलन प्रत्याशित है, जिसमें सिर्फ परिकल्पित निवेश शामिल हैं। ये वास्तविक प्राप्त/प्रयुक्त आंकड़ों से भिन्न हैं।

सारणी 5: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का उद्योग-वार वितरण: 2008-09 से 2017-18

उद्योग	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18	
	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सा	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सा	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सा	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सा	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सा	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सा	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सा	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सा	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सा	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सा
इन्फ्रास्ट्रक्चर	97	45.0	100	49.0	120	53.7	107	47.4	82	47.8	87	39.7	74	48.9	109	72.0	204	62.5	147	52.9
i) बिजली	54	27.9	75	30.7	104	46.2	82	42.4	71	39.4	70	35.1	65	42.2	93	57.2	170	45.4	122	38.2
ii) दूरसंचार	6	10.9	6	16.4	2	5.7	1	0.0	2	5.6	1	-	1	4.9	1	0.2	1	-	-	-
iii) बंदरगाह एवं एयरपोर्ट	4	2.8	2	0.3	1	0.7	1	1.3	1	1.9	1	0.8	-	-	3	2.4	8	5.7	6	3
iv) भंडारण एवं जल प्रबंधन	2	-	2	0.9	1	0.0	12	0.5	-	-	5	1.1	2	0.6	4	4.2	6	3.7	2	0.3
v) एसईजेड, औद्योगिक, बायोटेक तथा आई टी पार्क	28	3.2	15	0.6	12	1.1	11	3.2	8	0.9	8	1.5	3	0.9	1	0.4	2	0.4	1	1.6
vi) सडकें एवं पुल	3	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.2	3	0.3	7	7.6	17	7.3	16	9.8
रसायन एवं कीटनाशक	27	1.7	28	0.8	27	1.3	17	3.5	19	1.1	15	1.0	7	2.6	11	1.6	10	2.1	23	11.1
धातु एवं धातु के उत्पाद	97	17.7	134	18.1	113	21.1	73	16.3	51	28.9	44	17.0	17	17.4	14	1.5	23	4.9	21	9.5
निर्माण	30	10.8	20	11.5	18	3.3	22	1.7	20	2.8	27	2.1	29	4.0	26	1.8	60	12	39	5.1
परिवहन सेवाएँ	14	1.0	22	1.4	14	0.6	19	2.7	16	1.7	15	0.5	5	0.6	10	1.2	12	0.4	16	4
वस्त्र	45	1.2	77	2.2	77	2.9	94	7.0	31	1.9	58	10.3	50	4.1	49	4.8	57	4.1	54	3.6
होटल एवं रेस्तरां	57	2.8	56	2.6	63	3.5	51	4.6	31	3.1	29	2.7	15	1.1	16	1.1	12	0.8	29	2.8
खाद्य पदार्थ	50	1.0	41	0.5	39	0.7	41	1.5	36	0.9	43	1.8	34	2.9	26	1.8	38	0.9	47	2.7
अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएँ	16	0.5	23	0.9	22	0.6	9	0.3	17	1.4	10	0.7	2	0.1	1	0.0	22	1.1	18	1.7
कांच और मिट्टी के बर्तन	6	0.3	9	0.2	6	0.4	10	1.3	3	-	11	0.3	19	0.7	8	0.5	19	0.6	20	0.8
सीमेंट	28	6.0	29	2.8	14	2.4	9	2.0	11	3.9	12	7.1	7	3.8	5	1.9	5	2.3	3	0.6
खनन और उत्खनन	7	0.6	10	2.5	1	0.2	4	0.2	2	0.1	1	0.6	2	0.1	10	2.7	4	0.4	1	0.4
पेट्रोलियम उत्पाद	4	0.1	2	1.3	3	2.6	3	1.2	-	-	1	0.5	1	3.4	2	2.0	2	0.5	1	0.3
परिवहन उपस्कर और कलपुर्ज़े	30	3.0	25	1.3	28	0.8	26	2.6	17	0.9	16	1.2	7	5.3	4	2.5	9	3.6	10	0.3
बिजली के उपस्कर	17	1.3	16	0.2	24	2.0	12	0.3	10	1.9	9	2.0	7	0.2	3	0.2	9	0.2	6	0.2
चीनी	21	1.2	21	0.8	21	0.8	12	1.1	5	0.5	8	0.8	6	1.3	5	0.4	2	0.1	1	0.1
अन्य*	162	5.9	116	4.0	107	3.1	127	6.3	63	3.1	86	11.7	44	3.5	47	4.0	53	3.5	54	3.9
कुल	**708**	**100**	**729**	**100**	**697**	**100**	**636**	**100**	**414**	**100**	**472**	**100**	**326**	**100**	**346**	**100**	**541**	**100**	**490**	**100**
परियोजनाओं की कुल लागत बिलियन में	**3,111**		**4,095**		**3,752**		**1,916**		**1,895**		**1,273**		**873**		**918**		**1,792**		**1,728**	

*: इनमें औषधि एवं ड्रग्स, कृषि और उससे संबंधित क्रियाकलाप, कागज़ एवं कागज़ के उत्पाद, छपाई एवं प्रकाशन, रबड़ आईटी साफ्टवेयर, संचार एवं व्यापार सेवाएँ, मनोरंजन आदि जैसे उद्योग शामिल हैं।
-: कुछ नहीं / नगण्य।

सारणी 6: बैंकों /वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का आकार-वार वितरण: 2008-09 से 2017-18

अवधि	परियोजनाओं की संख्या और हिस्सा	₹1 बिलियन से कम	₹1 बिलियन से ₹5 बिलियन तक	₹5 बिलियन से ₹10 बिलियन तक	₹10 बिलियन से ₹50 बिलियन तक	₹50 बिलियन और उससे अधिक	कुल
2008-09	परियोजनाओं की संख्या	420	194	35	48	11	**708**
	प्रतिशत हिस्सा	5.1	14.1	7.5	29.7	43.7	**100 (3,111)**
2009-10	परियोजनाओं की संख्या	439	189	40	39	22	**729**
	प्रतिशत हिस्सा	3.8	11.0	6.8	20.8	57.5	**100 (4,095)**
2010-11	परियोजनाओं की संख्या	412	172	42	51	20	**697**
	प्रतिशत हिस्सा	4.4	10.2	8.6	29.3	47.5	**100 (3,752)**
2011-12	परियोजनाओं की संख्या	420	145	36	26	9	**636**
	प्रतिशत हिस्सा	8.3	17.0	13.7	27.6	33.4	**100 (1,916)**
2012-13	परियोजनाओं की संख्या	245	119	20	23	7	**414**
	प्रतिशत हिस्सा	4.8	14.6	7.3	26.8	46.4	**100 (1,895)**
2013-14	परियोजनाओं की संख्या	306	115	25	21	5	**472**
	प्रतिशत हिस्सा	8.3	20.0	13.9	29.1	28.7	**100 (1,273)**
2014-15	परियोजनाओं की संख्या	223	65	18	19	1	**326**
	प्रतिशत हिस्सा	9.0	16.6	14.6	47.8	12.0	**100 (873)**
2015-16	परियोजनाओं की संख्या	214	76	34	21	1	**352**
	प्रतिशत हिस्सा	8.6	20.9	26.0	38.5	5.9	**100 (918)**
2016-17	परियोजनाओं की संख्या	287	180	29	40	5	**541**
	प्रतिशत हिस्सा	5.8	23.3	11.9	41.7	17.4	**100 (1,792)**
2017-18	परियोजनाओं की संख्या	263	149	31	44	3	**490**
	प्रतिशत हिस्सा	5.1	20.5	11.7	44.1	18.6	**100 (1,728)**

टिप्पणी: i. कोष्ठकों के आंकड़े परियोजनाओं की कुल लागत ₹ बिलियन में दर्शाते हैं।

ii. प्रतिशत शेयर कुल परियोजना लागत में हिस्सा है।

सारणी 7: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार वितरण: 2008-09 से 2017-18

राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18	
	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सा	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सा	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सा	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सा	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सा	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सा	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सा	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सा	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सा	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सा
महाराष्ट्र	110	18.1	117	10.0	71	7.4	86	19.1	67	10.7	76	19.7	38	14.8	36	9.4	57	8.8	65	22.6
कर्नाटक	44	2.4	42	1.4	40	7.2	39	12.0	20	1.6	39	6.2	27	5.4	21	6.2	52	6.8	66	10.4
आंध्र प्रदेश	74	7.6	73	7.1	65	11.4	52	5.1	35	5.7	37	4.0	24	8.1	33	12.3	47	8.0	22	9.7
गुजरात	75	18.4	69	3.2	65	9.6	75	9.0	58	5.6	66	14.5	71	9.5	61	15.1	102	23.0	71	7.8
तमिलनाडु	63	2.3	66	5.5	93	6.1	58	5.7	22	1.8	33	5.4	27	2.9	26	9.3	22	4.4	28	6.5
राजस्थान	22	0.6	23	2.9	28	0.8	49	4.9	41	5.3	24	1.4	29	11.1	10	0.9	23	2.8	33	6.1
छत्तीसगढ़	16	2.3	23	6.0	31	12.1	11	2.4	9	4.1	16	10.7	8	7.4	8	4.7	15	4.0	7	4.6
उड़ीसा	15	9.0	25	13.9	25	7.4	15	6.3	10	26.8	10	11.7	5	15.9	6	3.1	6	3.1	5	2.9
उत्तर प्रदेश	32	3.1	27	0.4	32	4.6	42	7.8	26	4.4	21	1.1	20	5.4	15	2.3	22	3.7	30	2.4
हिमाचल प्रदेश	18	0.5	19	0.6	13	0.8	7	0.5	5	0.3	3	1.8	3	0.1	8	1.4	1	0.0	8	2.2
पंजाब	23	0.7	23	0.4	38	1.1	37	1.7	12	10.9	28	1.5	6	0.3	11	1.7	29	2.1	36	2.1
जम्मू कश्मीर	-	-	2	0.1	3	0.1	5	0.2	10	0.2	10	5.2	2	0.1	9	0.2	3	0.1	8	1.9
तेलंगाना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3.8	52	6.8	17	1.8
पश्चिम बंगाल	43	3.0	33	2.6	29	3.3	19	4.9	13	1.0	12	1.2	9	1.3	14	3.1	18	1.7	14	1.8
मध्य प्रदेश	20	7.2	23	4.2	21	5.2	16	5.6	13	3.9	30	6.1	14	3.9	21	6.9	18	7.5	12	1.5
विविध#	55	19.0	45	29.0	48	16.2	34	4.5	15	7.7	21	6.9	10	9.5	13	13.5	17	11.8	17	8.1
अन्य*	98	5.8	119	12.7	95	6.7	91	10.3	58	10.0	46	2.6	33	4.3	44	6.1	57	5.4	51	7.6
कुल	**708**	**100**	**729**	**100**	**697**	**100**	**636**	**100**	**414**	**100**	**472**	**100**	**326**	**100**	**346**	**100**	**541**	**100**	**490**	**100**
परियोजनाओं की कुल लागत (₹ बिलियन में)	**3,111**		**4,095**		**3,752**		**1,916**		**1,895**		**1,273**		**873**		**918**		**1,792**		**1,728**	

#: इनमें कई राज्यों की परियोजनाएं शामिल हैं।

*: इनमें शेष राज्य / संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

' -': सूचना उपलब्ध नहीं है

टिप्पणी : प्रतिशत शेयर कुल परियोजना लागत में हिस्सा है।

सारणी 8: 2010-11 से 2017-18 के दौरान बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का प्रयोजन-वार वितरण

अवधि	परियोजनाओं की संख्या और हिस्सा	नई	विस्तार एवं आधुनिकीकरण	विविधीकरण	अन्य	कुल*
2010-11	परियोजनाओं की सं.	454	224	6	13	**697**
	प्रतिशत हिस्सा	66.8	30.9	1.8	0.5	**100 (3,752)**
2011-12	परियोजनाओं की सं.	449	172	5	10	**636**
	प्रतिशत हिस्सा	70.6	23.1	0.1	6.3	**100 (1,916)**
2012-13	परियोजनाओं की सं.	303	107	-	4	**414**
	प्रतिशत हिस्सा	84.2	14.7	-	1.1	**100 (1,895)**
2013-14	परियोजनाओं की सं.	361	95	2	14	**472**
	प्रतिशत हिस्सा	65.2	20.1	-	14.7	**100 (1,273)**
2014-15	परियोजनाओं की सं.	203	92	2	29	**326**
	प्रतिशत हिस्सा	39.4	14.7	0.2	45.7	**100 (873)**
2015-16	परियोजनाओं की सं.	260	64	3	19	**346**
	प्रतिशत हिस्सा	73.6	14.3	0.1	12	**100 (918)**
2016-17	परियोजनाओं की सं.	429	97	4	11	**541**
	प्रतिशत हिस्सा	78.6	9.9	0.1	11.3	**100 (1,792)**
2017-18	परियोजनाओं की सं.	401	80	2	7	**490**
	प्रतिशत हिस्सा	89.3	9.2	0.1	1.4	**100 (1,728)**

टिप्पणी: i. कोष्ठकों के आंकड़े ₹ बिलियन में परियोजनाओं की कुल लागत हैं।
ii. - : कुछ नहीं / नगण्य।